

2



अविध शराब
परिवहन के
विरुद्ध कार्यवाही

5



आर्थिक कठिनाइयों
से भी हारें नहीं,
संसद पहुंचें

7



पत्रकारों की
ताकत उनकी
कलम है

सभी सुधि पाठकों
को गणतंत्र
दिवस की हार्दिक
शुभकामनाएं

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 38

प्रति सोमवार, 27 जनवरी 2025

मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

मप्र में त्यापमं घोटाले से बड़ा महाघोटाला है भूपेन्द्र सिंह का परिवहन घोटाला

सौरभ शर्मा तो केवल चूहा है, बड़े अजगर का बाहर आना बाकी है

कवर स्टोरी

-विजया पाठक

एडिटर

पूर्व परिवहन मंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाने वाले अजगर नेता भूपेन्द्र सिंह की मुश्किलें बढ़ती आ रही हैं। पहले जनगणना आवास विभाग में हुये कटाघार को लेकर पार्ल में आये भूपेन्द्र सिंह एक बार फिर परिवहन विभाग में हुये मध्योत्तर को लेकर फिर से संसद के फेरे में खड़े हो गये हैं। पार्ल इस बात को लेकर भी है भूपेन्द्र सिंह का नाम सौरभ शर्मा एवं परिवहन विभाग में हुये कटाघार को अकल नंबर पर आ रहा है। यह पूरा घोटाला परिवहन मंत्री भूपेन्द्र सिंह के इशारे पर हुआ है। इसका मास्टर भूपेन्द्र सिंह का दिमाग ही है। अब जब एक के बाद एक अधिकारियों और नेताओं के नाम सनाने आने लगे तो प्रदेश सरकार से लेकर केंद्रीय मंत्री स्तर तक के नेताओं को नींद उड़ गई है।



उप नेता प्रतिपक्ष ने पेश किये महत्वपूर्ण दस्तावेज

सौरभ शर्मा मामले में पूर्व परिवहन मंत्री भूपेन्द्र सिंह को चुनौती के जवाब में कांग्रेस ने मम्मले से जुड़े दस्तावेज जारी किए हैं। विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने आरोप लगाया है कि 'परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की अनुकूल नियुक्ति के मामले में पूर्व परिवहन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने ही नियम विरुद्ध तरीके से अनुरोध को धी और इसके बाद विभाग में उसे नियुक्ति दी गई। हेमंत कटारे ने कहा कि वे इससे जुड़े दस्तावेज लोकसभ के सौंपेंगे। पूर्व परिवहन मंत्री और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करने की मांग करेंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विभाग में नियुक्ति के पहले ही सौरभ शर्मा चेंक पोस्ट पर उग्राही का काम करत था। उसके इसे हुनर को देखकर पूर्व मंत्री ने उसे परिवहन विभाग में नियुक्ति कराई। अब एसीसियां सौरभ शर्मा को इम्पेडर खोजकर रिफरार नहीं कर रहीं, ताकि बड़े लोगों को पोल न खुल सके।

हेमंत कटारे का भूपेन्द्र सिंह पर बड़ा आरोप

सौरभ शर्मा फंका है, यह प्रदेश की पुलिस अब तक पता ही नहीं कर पाई, या यह भी हो सकता है कि एसीसियां उसे फंकार रखे हुए हैं, ताकि बड़े लोगों की पोल न खुल सके। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पूर्व परिवहन मंत्री भूपेन्द्र सिंह की कृपा से ही सौरभ शर्मा को परिवहन विभाग में पदस्थ किया गया। उनकी ही कृपा से ही आरक्षक होते हुए भी सौरभ शर्मा को बड़े चेंक पोस्ट पर तैनात रखा गया। जिन चेंक पोस्ट पर इम्पेडर को तैनात होना चाहिए, ऐसे कर्ज पोस्टों पर अकेले सौरभ शर्मा को प्रभार सौंपा गया। भूपेन्द्र सिंह परिवहन विभाग से नगरीय प्रशासन मंत्री बने, तब भी सागर के मालवीन चेंक पोस्ट का विम्वम सौरभ शर्मा को दिया गया। भूपेन्द्र सिंह के स्टफा में पदस्था सेनर के माध्यम से सौरभ शर्मा से कलेक्शन किया जाता था। (शेष पेज 2 पर)

छत्तीसगढ़ ही नहीं पड़ोसी राज्यों में भी छाया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जलवा

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने निर्विवाद, साफ और सरल छवि के चलते न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्यों में भी लोकप्रिय हैं। उनकी इसी लोकप्रियता के चलते भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने लोकसभा के चुनाव प्रचार में अपना प्रमुख चोहर बनाया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का चोहरा और जलवा छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्यप्रदेश, ओडिशा और झारखंड में छाया हुआ है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान सौरभ साय ने कुल 53 दिन में 64 जनसभा समेत कुल 117 सभाएं ली हैं। इस दौरान उनके तेवर पूरी तरह आक्रामक रहे और वे कांग्रेस और इंडिया गलबंधन पर जितने हमलावर रहे उतना ही उन्होंने मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और मोदी की गारंटी की लोगों के बीच चर्चा भी की। (शेष पेज 6 पर)



संविधान की मूल भावना को समझने और बचाने की जरूरत

(पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का विशेष आलेख पेज 2 पर)

बड़ा सवाल: जब निवेश घरतल पर नहीं उतर रहा तो फिजूलखर्ची का क्या मतलब?

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश को उद्योग की सुई से मजबूत बनाने और औद्योगिक नगरी का स्थान सज्जे अग्रे बढ़ रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को लगाना एक वर्ष से अधिक का समय ले गया है। अगर हम मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस एक वर्ष का विस्तार से अंकन करते तो यह समझ आता है कि मोहन यादव ने प्रदेश में केवल और केवल औद्योगिक विस्तार पर सबसे अधिक ध्यान देकर के काम करना अटका किया है।

बड़े-बड़े इवेंट से नहीं, नियत, नियम और विजन से आता है निवेश सबसे पहले कमलनाथ ने दी थी देश में औद्योगिक विस्तार की संकल्पना



देने का कार्य कर रहे हैं यह सपना कभी मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने देखा था। कमलनाथ ने केंद्र में उद्योग मंत्री

आज यह बात इसलिए करने का विषय उठा है क्योंकि मोहन यादव जिस सपने को आज अकार

रहते हुए प्रदेश और देश विकास की एक ऐसी संकल्पना देखी थी जिस पर कांग्रेस की केंद्र सरकार तो कार्य नहीं कर सकी लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अब सवाल यह उठता है कि जिस औद्योगिक विस्तार के कार्य को भाजपा अपना बता रही है वह आखिर किसका है? सरकार इसे अपना बताती है तो जानकार इसे कमलनाथ की सफलता बता रहे हैं।

कमलनाथ ने दिया था औद्योगिक विस्तार का मंत्र



खास बात यह है कि जब कमलनाथ केंद्र में मंत्री थे तभी उन्होंने तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्रियों को प्रदेश में उद्योग लाने का मंत्र दिया था। इसके पीछे कमलनाथ की मंशा इतनी बस थी कि इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और हर युवा हर वर्ग के लोगों का काम मिलेगा। आज प्रदेश में जिस ढंग से जिलों जिलों में जाकर निवेश और उद्योग लगाने का कार्य किया जा रहा है इससे कहीं न कहीं प्रदेश की नींव को मजबूती मिलेगी और प्रदेश आगे बढ़ेगा। (शेष पेज 2 पर)



13 करोड़ की लागत से रामरेखा घाट की बदलेगी तस्वीर

-अमित राय

जगत प्रवाह. बक्सर। रामरेखा घाट पर पर्यटकीय सुविधाओं के विकास के लिए अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर सदर द्वारा पर्यटन विभाग के कनीय अभियंता एवं अन्य के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया। पर्यटन विभाग, बिहार द्वारा लगभग 13 करोड़ की लागत से रामरेखा घाट पर कैफेटेरिया, थिएटर एवं अन्य पर्यटकीय सुविधाओं का निर्माण कार्य किया जाना है। अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर सदर की अध्यक्षता में स्थलीय निरीक्षण किया गया।

अंचल अधिकारी बक्सर के द्वारा विकास कार्य हेतु भूमि का सत्यापन कर चिह्नित किया गया। इसके पश्चात वास्तुविद के द्वारा कार्य योजना बना कर अग्रसर कार्रवाई की जाएगी। जिला पदाधिकारी द्वारा रामरेखा घाट पर विकासात्मक एवं सौंदर्यीकरण हेतु सभी स्टेज होल्डर को तत्परतापूर्वक कार्य करते हुए यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिए गया। निरीक्षण के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर, अंचल अधिकारी बक्सर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरी। ब्लॉक कांग्रेस देवरी ने पूर्व मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार देवरी को ज्ञापन सौंपा। विधानसभा क्षेत्र देवरी में अधिकारियों की मनमानी, ग्राम पंचायत महाराजपुर को नगर पंचायत बनाने, क्षेत्र के स्कूलों का उन्नयन करने, सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति, अधोषिक्त विद्युत कटौती, आंकलित विद्युत बिलों पर रोक लगाने, क्षेत्र में अवैध जुआ, सट्टा, शराब पर रोक लगाने, सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण प्रणाली में हो रहे भ्रष्टाचार, तुसार से नष्ट फसलों का सर्वे करने सहित विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में समस्त किसानों द्वारा मांग की। सागर जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत महाराजपुर को नगर पंचायत बनाये जाने की मांग ग्रामीणों द्वारा लम्बे समय से की जा रही है। उपरोक्त मांग को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में देवरी विधानसभा की तीनों ग्राम पंचायतों महाराजपुर, केसली, गौरझामर, को नगर पंचायत बनाने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी लेकिन सरकार गिरने की बजह से लागू नहीं हो सकी, महाराजपुर



की जनसंख्या 15 हजार से अधिक एवं मतदाताओं की संख्या 9000-10000 के लगभग है। उक्त पंचायत के लगभग 20-25 वार्ड है, जो बहुत बड़े भू-भाग में फैली हुई है। उक्त ग्राम पंचायत की सीमा से लगे हुए अन्य ग्राम है जिसको मिलाकर एक बृहद नगर पंचायत घोषित की जा सकती है। विधानसभा क्षेत्र देवरी के विकासखण्ड देवरी में ग्रामीण अंचलों दूरदराज क्षेत्रों में हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल नहीं

हैं, जिस कारण अधिकांश छात्र/छात्राएं कक्षा- आठवीं व दसवीं के पश्चात अध्ययन करना बंद कर देती है और आगे की शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस प्रभारी पूर्ण विधायक घनश्याम सिंह, सह प्रभारी अधिपेक यादव, जिला कांग्रेस अध्यक्ष आनंद अहिरवार ब्लॉक कांग्रेस देवरी अध्यक्ष आशीष चावा राजौरिया, राजकुमार सिंह धनीरा सहित सैकड़ों किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान सक्रियता से संचालित



-कैलाशचंद्र जैन

जगत प्रवाह. विदिशा। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानि द्वारा "परवाह" थीम पर आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान अंतर्गत विदिशा जिलेवासियों को यातायात नियमों से जागरूक करने हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे, नगर पुलिस अधीक्षक अतुल कुमार सिंह के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान माह 2025 प्रवाह थीम के अंतर्गत नेत्र परीक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला चिकित्सालय विदिशा के डॉ. विवेक जैन नेत्र विशेषज्ञ एवं स्टॉफ द्वारा

स्वामी विवेकानंद चौराहा पर नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 60 वाहन चालकों के आंखों की निःशुल्क जांच की गई। इस शिविर का उद्देश्य वाहन चालकों को उनकी आंखों की सेहत के बारे में जागरूक करना और उन्हें सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में बताना था। डॉक्टरों ने वाहन चालकों को उनकी आंखों की जांच के बाद आवश्यक सलाह और सुझाव दिए। जिन वाहन चालकों को मोतियाबिंद, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, समस्या आंखों में थी उन्हें जल्द से जल्द चश्मा पहनने एवं मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने हेतु बताया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करना है।

आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। अवैध शराब के विक्रय निर्माण संग्रहण, परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश एवं जिला आबकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में अवैध शराब के विरुद्ध विशेष अभियान के अंतर्गत नर्मदापुरम शहर में सांगखेड़ा कला बीकोर मार्ग पर नाकेबंदी करने पर दो आरोपियों छोटेलाल पिता भगवान दास एवं सुरेश पिता सुखलाल निवासी सर्रा केसली थाना माखननगर के पास से लगभग पौने दो पेटे अंग्रेजी विस्की एवं रम शराब कुल 80 पाव बरामद किया गया। आरोपियों के खिलाफ मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 1 क के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर मदिरा एवं मोटरसाइकिल जप्त किया गया। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने हेतु जमानत मुचलके पर रिहा किया गया। जप्त मदिरा एवं मोटरसाइकिल की कीमत लगभग 60,000 आकी गई है।



नर्मदापुरम शहर में आबकारी टीम द्वारा सब्जी मंडी के समीप एक स्कूटी को संदेह के आधार पर रोककर तलाशी ली। तलाशी में स्कूटी से एक पेटे सादा शराब पाई गई। वाहन चालक आबकारी टीम को देखकर मौके से फरार हो गया। उक्त कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक सुयश फौजदार वृत्त नर्मदापुरम वी वासुदेवाचार्य

त्रिपाटी एवं मुख्य आरक्षक रघुवीर प्रसाद, यादव आबकारी आरक्षक योगेश कुमार आबकारी आरक्षक धर्मेन्द्र बारी, मोहन का विशेष योगदान था।

नहीं मिल पा रहा योजनाओं का लाभ, आधार कार्ड अपडेट नहीं होने से पेंशन भी रूकी -बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. गटसिंहपुर। जिले की जनपद पंचायतों के अंतर्गत 400 के लगभग पंचायत होने के बावजूद भी महिलाओं से आधार कार्ड सेंटर बंद पड़े हुए हैं। जिसका खामियाजा छात्रों, बुजुर्गों को उठाना पड़ रहा है। पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड बनाये जा रहे हैं। कुछ बैंक को भी आधार कार्ड सेंटर बनाये गए हैं जो गांव के लोगों को आधार कार्ड अपडेट करना है तो 60 से 70 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। सेंटर्स पर लाइन सुबह 8 बजे से लगने लगती है। सेंटर्स में 10 बजे के बाद ही काम चालू होता है। इस तरह छात्रों, महिलाओं बुजुर्गों वगैरों को आधार कार्ड अपडेट सुधारने एवं बनवाने के लिए भटकते रहते हैं एवं बार बार बंद आधार कार्ड सेंटर के चक्कर लगाने पड़ रहे

सम्पादकीय

कब तक भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ करेंगे बांग्लादेशी घुसपैठिये

दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशियों के फर्जी दस्तावेज बनाते वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। लगभग एक महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है जोर शोर से घुसपैठियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, एनसीआर सहित देश के प्रमुख महानगरों तथा देश के विशेष समुदाय की सैकड़ों बस्तियों में घुसपैठिये अवैध रूप से बस गए हैं। लाखों बांग्लादेशी घुसपैठिये और रोहिंग्या देश के लिये गंभीर सुरक्षा के लिये खतरा बन चुके हैं।

राजनैतिक कारण और कमजोर इच्छाशक्ति के चलते इस गंभीर विषय की अनदेखी की की गई। शायद ही भारत का कोई भी बड़ा शहर, कस्बा हो जहां सदिग्ध रूप से कुछ बाहरी लोग हाल ही में न बसे हो। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 1914 में भारत में अनुमानित बांग्लादेशियों की संख्या लगभग दो करोड़ बताई थी। इस प्रकरण का दुखद पहलू यह है कि घुसपैठ का मुद्दा केवल चुनाव के दौरान जोरशोर से उठता है परंतु चुनाव के बाद इसकी तीव्रता धूमिल हो जाती है। यदि हम देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो सबसे प्रमुख बात तो यह है कि दिल्ली सरकार और पुलिस से यदि पूछा जाए कि दिल्ली में कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं तो इसका उत्तर गोलमोल ही मिलता है।

शायद राज्यों की पुलिस को भी नहीं पता कि कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं? हालांकि हाल ही में एलजी के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा घुसपैठियों, रोहिंग्याओं के खिलाफ तलाशी अभियान शुरू किया गया है। अच्छी बात है अब आप शासित दिल्ली नगर निगम ने भी अपनी तरफ से अभियान शुरू करने का फैसला लिया है।

एलजी ने दिल्ली पुलिस को अवैध अप्रवासियों की

पहचान के लिए एक महीने तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करके आगे की कार्रवाई करने के लिये कहा है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी एजेंसियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि शहर में कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर कोई अनधिकृत कब्जा न हो जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है। इस दौरान बीते 22 दिसंबर तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जांच के दौरान मात्र 175 घुसपैठिये ही चिन्हित किये जा सके हैं। चूकि घुसपैठियों के खिलाफ अभियान सीमित अवध के लिए है ऐसे में घुसपैठिये दिल्ली छोड़कर आसपास के जिलों गजियाबाद आदि में भाग सकते हैं। ऐसे में फिर इस अभियान पर पलीता लगा सकता है। इसलिए जरूरत है एक समेकित, कारगर और दीर्घकालीन अभियान शुरू करने की।

इस प्रकरण का दूसरा नाकारात्मक पहलू यह है कि इस मुद्दे पर आप और भाजपा के बीच राजनैतिक बयानबाजी शुरू हो गई है जिससे इस अभियान की सफलता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है आप का यह बयान कि घुसपैठियों के बहाने भाजपा पूर्वांचल निवासियों पर निशाना साध रही है जो कि बिल्कुल तथ्य से परे है। ऐसे बयानों से अभियान की तीव्रता बाधित हो सकती है। जब एलजी और एमसीडी दोनों अपनी अपनी ओर से घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं तो ऐसे में विरोधाभासी बयान की क्या आवश्यकता है। घुसपैठिए दिल्ली-एनसीआर में हत्या, लूट, डकैती, चोरी और अन्य आपराधिक वारदात के जरिए अपराध का ग्राफ भी बढ़ा रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा करने में भी पीछे नहीं हैं। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था बिगाड़ने के मकसद से नकली नोटों का कारोबार करने और सभी तरह के ड्रग्स की तस्करी भी करते हैं।

सियासी गहमागहमी

क्या शराबबंदी का फैसला लागू कर पायेंगे मुख्यमंत्री?



मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश को शराब मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री पद संभालने से लेकर अभी तक मुख्यमंत्री यादव ने ऐसे कई फैसले लिये हैं लेकिन अफसोस यह है कि अभी तक यह फैसले धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब

बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों महेश्वर में प्रदेश में शराबबंदी लागू करने का ऐलान किया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या मुख्यमंत्री सही ढंग से इसे लागू करने में सफल होंगे या एक बार फिर यह घोषणा सिर्फ घोषणावीर मुख्यमंत्री की सूची में शामिल हो जायेगी।

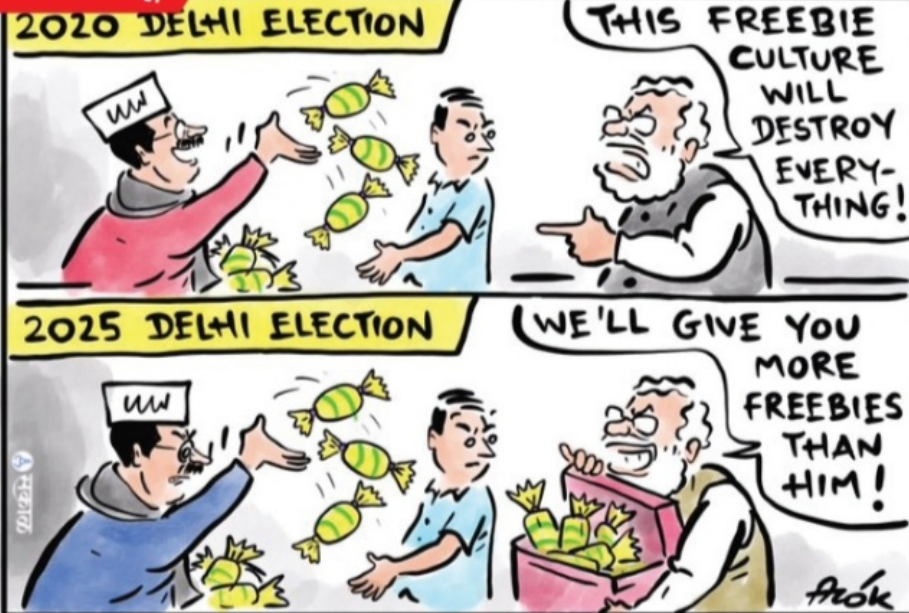
पटवारी को नहीं मिल रहा अपनों का साथ



27 जनवरी को बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली महू में कांग्रेस इस साल की पहली और सबसे बड़ी रैली निकालने जा रही है। इसके लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 15 विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें पूरे प्रदेश से 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य दिया गया है।

बात यह है कि जीतू पटवारी और उमंग सिंधार खुद एक-एक जिले का दौरा कर रहे हैं। कारण है इस रैली में मल्लिकार्जुन खड्गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ-साथ कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी शामिल होने वाले हैं। सभी बड़े नेताओं का शामिल होना कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन पटवारी को अपनों का ही साथ नहीं मिल पा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि पटवारी अब इस रैली को कैसे सफल बना पाते हैं।

हफ्ते का कार्टून



ट्वीट-ट्वीट

बेटियां शक्ति, सहस्र और समर्पण का प्रतीक हैं, अपने बेहतर कल के लिए वे उम्मीद और आकांक्षाओं से भरी होती हैं।

हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए एक उज्वल और सुरक्षित भविष्य तैयार करें, आधी आबादी को पूरा हक दिलाने का संकल्प लें।

-राहुल गांधी

काबुल नेता @RahulGandhi



संविधान बचाने आगे आओ, बापू-अंबेडकर का देश बचाओ !!
जय बापू - जय माँ - जय संविधान



पल्लो महू
27 जनवरी 2025
घात: 11 बजे

-कमलनाथ

पट्टे काबुल अजय
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

आर्थिक कठिनाइयों के बाद भी हार नहीं मानी और संसद की सीढ़ियों तक पहुंचे खटीक

समता पाठक/जगत प्रवाह



मोदी 3.0 मंत्रिमंडल गठन में शामिल वीरेंद्र कुमार खटीक आठवीं बार सांसद बने। वहीं एक बार फिर मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ले चुके। वह चार बार सागर से और चार बार टीकमगढ़ से लोकसभा चुनाव जीते हैं। 1977 से राजनीति में जुड़े डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक का राजनीति सफर बहुत ही लंबा है। वह 1977 में रीवा संयोजक थे, 1979-82 से वे मंडल संगठन सचिव रहे। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा की राजनीति शुरू की। 1982 से 84 तक वे सागर जिले के महासचिव रहे। 1987 में बजरंग दल के सागर जिले के संयोजक बने। 1991 में भाजपा में सागर के सचिव बनाए गए। 1994 में भाजपा के राज्य प्रतिनिधि बने। 1996 में पहली बार सांसद चुने गए। उनकी सक्रियता को देखते हुए उन्हें श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया। 1998-99 में वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की परामर्श दाय्री समिति के सदस्य बने। 1998 में दूसरी बार सांसद चुने गए। 1999 में तीसरी बार सांसद बनने का मौका मिला।

2004 में बतौर सांसद चौथा कार्यकाल शुरू किया। इस दौरान वे श्रम संबंधी समिति में सदस्य रहे, विशेषाधिकार समिति में सदस्य रहे। 2006-08 में भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष रहे। 2009 में पांचवीं बार सांसद बने। मई 2014 में छठी बार सांसद चुने गए। टीकमगढ़ और सागर की जनता पर राज कर रहे डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक का जीवन आसान नहीं था। वह बहुत ही मध्यम परिवार से आते हैं। 27 फरवरी 1954 में सागर में जन्मे डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक बेहद गरीब परिवार से थे।

उनका जीवन काफी संघर्षों से भरा रहा, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई पूरी कर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1987 में उन्होंने कमल वीरेंद्र के साथ सात फेरे लिए। उनके परिवार में तीन बेटे और एक बेटा है। शुरू से खेती किसानों से जुड़े वीरेंद्र कुमार खटीक 02 करोड़ 88 लाख की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। मोदी कैबिनेट में शपथ लेने वाले वीरेंद्र कुमार खटीक उच्च शिक्षित हैं। उन्होंने अपनी मेहनत की दम पर सागर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है।

गरीबी के वजह से वीरेंद्र कुमार खटीक को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। शुरूआती दिनों में वो सागर में अपने पिता के साथ साइकिल-स्कूटर पंचर ठीक करने का काम करते थे, उनके पास एक पुराना स्कूटर हुआ करता था, जिसपर वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में घूमते थे। वह शुरू से ही अपने सादगी को लेकर जाने जाते हैं। इसी वजह से केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद वह कई बार बिना सुरक्षा के घर के बाहर निकल जाते थे। यह तक कि कई बार वे आम जनता की तरह मार्केट में सब्जियां खरीदते भी देखे गए।

समस्त देशवासियों को आजादी के महापर्व

26 जनवरी
समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।

हर्ष यादव महासचिव, म.प्र. कांग्रेस कमेटी, पूर्व कोबिनेट मंत्री एवं विजय श्री गैस एजेंसी देवरी।

मान.प्रहलाद सिंह पटेल कोबिनेट मंत्री म.प्र.शासन

26 जनवरी

डॉ.जयवीर मिश्रा सागरक बीकेपी कोबिनेट देवरी

जो मरता नहीं है नहीं ले, वहती जिसमें रसदार नहीं। वह हुदय नहीं फटते है, जिसमें खरीद का पार नहीं।

समस्त देशवासियों को

गणतंत्र दिवस 26

आन देश की शान देश की इस देश की हम संतान हैं, तीन रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है।

26 जल ही जीवन है इसे बर्बन न वहायें। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। साफ सुचर मेरा नम, देव मेरा सुचर हो, प्यार फैले राडकों पर, खहरा ठिबे को अंदर हो।

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

सीजीपी, नेतृ अजयवत वैन अजय, सागरपालिका देवरी

नरुंधराजीर खान अजयक, सागरपालिका देवरी

संजय सिंह नगपुरी सीधेपको अजयपालिका देवरी

सीजन्य से:- समस्त पार्थदगण एवं समस्त स्टाप नगटपालिका परिषद देवरी।

नोबल परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को

नोबल परिवार की शैक्षणिक संस्थाएं

- नोबल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सागर
- नोबल कॉलेज, सागर (डिग्री कॉलेज)
- नोबल डिस्टेंस लर्निंग सेंटर (चिबकूट, माखनगला, भोज वि.वि.)
- नोबल फिल डेवलपमेंट सेंटर (WSDC), सागर
- नोबल पब्लिक स्कूल, देवरी (Affiliated to CBSE)
- WIOS स्टीड सेंटर, देवरी
- नोबल कॉलेज, देवरी
- नोबल फिल डेवलपमेंट सेंटर (WSDC), देवरी
- नोबल पब्लिकेशन

गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें...

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नर्मदापुरम (म.प्र.)

यातायात के नियमों का पालन करें कृपया हेनमेट का प्रयोग करें

गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें...

वन विभाग नर्मदापुरम (म.प्र.)

पेड़ लगाएं जीवन बचाएं

गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें...

जनपद परिषद नर्मदापुरम (म.प्र.)

गांव हमारी धरोहर

गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें...

विपणन विभाग नर्मदापुरम (म.प्र.)

स्वच्छ जिला, स्वच्छ राज्य, स्वच्छ देश

ट्रंप ने दिया जलवायु संधि को झटका



प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार संभालते ही ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। बतौर राष्ट्रपति पहले ही दिन ट्रंप ने पेरिस जलवायु संधि से अलग होने का निर्णय ले लिया है। अमेरिका अब विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का सदस्य भी नहीं रहेगा। अमेरिका में अब जन्मजात नागरिकता का अधिकार लागू नहीं होगा। अब तक यहां जन्म लेने के साथ ही शिरा को नागरिकता मिल जाती है। ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन से जुड़े पेरिस समझौते से हटने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा है कि 'मैं तुरंत पेरिस जलवायु संधि से हट रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका अपने उद्योगों को उस स्थिति में खाने नहीं पहुँचाएगा, जब अन्य देश बेखोफ होकर प्रदूषण फैला रहे हों।' याद रहे ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल 2017 में भी इस संधि से देश को अलग कर लिया था। परंतु जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका फिर इसमें शामिल हो गया था। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचने के लिए वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के उद्देश्य से दुनिया के 175 देशों ने यह हस्ताक्षरित समझौता किया हुआ है। अब अमेरिका के एक बार फिर से अलग हो जाने से दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की पहल

को झटका लगेगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में 2015 में हुए ऐतिहासिक 'पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते' को बढ़ा झटका लगा है। इस समझौते पर भारत-चीन 175 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुए समझौतों को ट्रंप जैसे लोग अपनी आत्मकेंद्रित दृष्टि के चलते खारिज करने लग जाएंगे तो न तो भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं का कोई महत्व रह जाएगा और न ही वैश्विक समस्याओं पर आगे कोई सहमति बन पाएगी। इस नाते अमेरिका का इस वैश्विक कठार से बहार आना दुनिया के सुखद भविष्य के लिए अहंकार संकेत नहीं है। जबकि अमेरिका सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले देशों में प्रमुख है। राष्ट्र संघ को अमेरिका के डब्ल्यूएचओ से बाहर हो जाने पर भी बढ़ा झटका लगेगा, क्योंकि प्रकृतिक आपदा और युद्ध की स्थिति में प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में अमेरिका यूएन को बड़ी मदद करता रहा है।

इस करार से अमेरिका का बहार आना समूचे विश्व के लिए अशुभ है। अपने औद्योगिक हितों की चिंता और चुनावी वादे की सनक पूर्ति के लिए ट्रंप ने यह पहल की है। दरअसल ट्रंप अमेरिकी कंजरवेटिव पार्टी के उस धड़े से सहमत रहे हैं, जो मानता है कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ता वैश्विक तापमान एक शोथी आशंका है। इसीलिए ये लोग कार्बन उत्सर्जन में कटौती से अमेरिका के औद्योगिक हित प्रभावित होने की पैरवी करते रहे हैं। इस मुद्द की इन्हीं धरणाओं के चलते ट्रंप ने चुनाव में 'अमेरिका फस्ट' और 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' का नारा दिया था। इस फैसले से मुकर जाने के कारण दुनिया भर में ट्रंप की निंदा हो रही है।

दरअसल ट्रंप की इस आत्मकेंद्रित मानसिकता का तभी अंदाजा लग गया था, जब भारत और चीन पर आरोप लगाया था कि इन दोनों देशों ने

विकसित देशों से अरबों डॉलर की मदद लेने की शर्त पर समझौते पर दस्तखत किए हैं। लिहाजा यह समझौता अमेरिका के आर्थिक हितों को प्रभावित करने वाला है। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में यहां तक कहा था कि संयुक्त राष्ट्र की 'हरित जलवायु निधि' अमेरिका से कम हथियाने की साजिश है। ट्रंप की इस सोच से पता चलता है कि अमेरिका अब वैश्विक समस्याओं के प्रति उदार रुख नहीं अपनाएगा? अजरबैजान की राजधानी बाकू में जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन पर अंकुश के लिए आयोजित हुए कॉप-29 शिखर सम्मेलन में ही यह अंदाजा लग गया था कि डोनाल्ड ट्रंप पना: राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, अतएव जीवाश्म ईंधन पर अंकुश की प्रक्रिया को पलीता लग सकता है? ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही इस संदेह को हकीकत में बदल दिया है। ट्रंप जीवाश्म ईंधन के प्रबल पक्षधर रहे हैं। इसलिए वे पर्यावरण संकट को कोई खतरा न मानते हुए, इसे पर्यावरणविदों द्वारा खड़ा किया गया एक होवा भर मानते हैं। ट्रंप और उनके समर्थक नेताओं का समूह अधिकतम जीवाश्म ईंधन पैदा करने की वाकालात करते रहे हैं। जबकि पेरिस समझौते पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने न केवल दस्तखत किए थे, बल्कि संधि के प्रावधानों का अनुमोदन भी किया था।

जलवायु सम्मेलन कॉप-29 में कोयले, तेल और गैस अर्थात् जीवाश्म ईंधन का उपयोग धीरे-धीरे खत्म करने की पैरवी पर्यावरण विज्ञानी कर रहे थे, जिससे बढ़ते वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक केंद्रीत किया जा सके। अनेक देशों ने 2030 तक दुनिया की नवीनीकरण योग्य ऊर्जा को बढ़ाकर तीन गुना करने के सुझाव दिए थे। इसके अंतर्गत अक्षय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत सूर्य, हवा और पानी से बिजली बनाना है। इस सिलसिले में प्रेरणा लेने के लिए ऊरुग्वे जैसे देश का उदाहरण दिया गया, जो अपनी जरूरत की 98 फीसदी ऊर्जा इन्हीं स्रोतों से प्राप्त करता है।

लेकिन यह एक अपवाद है, हकीकत यह है कि यूक्रेन और रूस तथा इजरायल और हमास के बीच चलते भीषण युद्ध के कारण कोयला जैसे जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा उत्पादन का प्रयोग बढ़ा है और बिजली उत्पादन के जिन कोयला संयंत्रों को बंद कर दिया गया था। उनका उपयोग फिर से शुरू हो गया है।

2018 ऐसा वर्ष था, जब भारत और चीन में कोयले से बिजली उत्पादन में कमी दर्ज की गई थी। नतीजतन भारत पहली बार इस वर्ष के 'जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक' में शीर्ष दस देशों में शामिल हुआ था। वहीं अमेरिका सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल हुआ था। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 'कॉप 25' जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में यह रिपोर्ट जारी की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 57 उच्च कार्बन उत्सर्जन वाले देशों में से 31 में उत्सर्जन का स्तर कम होने के रूझन इस रिपोर्ट में दर्ज थे। इन्हीं देशों से 90 प्रतिशत कार्बन का उत्सर्जन होता रहा है। इस सूचकांक ने तय किया था कि उत्सर्जन की खपत में कमी सहित कार्बन उत्सर्जन में वैश्विक बदलाव दिखाई देने लगे हैं। इस सूचकांक में चीन में भी मामूली सुधार हुआ था। नतीजतन यह तीसरे स्थान पर रहा था। जी-20 देशों में ब्रिटेन सातवें और भारत को नववाँ उच्च श्रेणी हासिल हुई थी। जबकि आस्ट्रेलिया 61 और सऊदी अरब 56वें क्रम पर रहे थे। अमेरिका खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में इसलिए आ गया था, क्योंकि तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन की शिल्वली उड़ते हुए इस समझौते से बाहर आ गए थे। हकीकत है कि अमेरिका ने वास्तव में कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण के कोई प्रयास ही नहीं किए। दुनिया की लगभग 37 प्रतिशत बिजली का निर्माण थर्मल पावरों में किया जाता है। इन संयंत्रों की भट्टी में कोयले को झोंका जाता है, तब कहीं जाकर बिजली का उत्पादन होता है।

इन बदलते हालातों में हमें जिंदा

रहना है तो जिंदगी जीने की शैली को भी बदलना होगा। हर हाल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करनी होगी। यदि तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक काल के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है तो कार्बन उत्सर्जन में 43 प्रतिशत कमी लानी होगी। आईपीसीसी ने 1850-1900 की अवधि को पूर्व औद्योगिक वर्ष के रूप में रेखांकित किया हुआ है। इसे ही बढ़ते औसत वैश्विक तापमान की तुलना के आधार के रूप में लिया जाता है। गोया, कार्बन उत्सर्जन की दर नहीं घटी और तापमान में 1.5 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो असमय लकनी, सूखा, बाढ़ और जंगल में आग की घटनाओं का सामना निरंतर करते रहना पड़ेगा। बढ़ते तापमान का असर केवल धरती पर होगा, ऐसा नहीं है। समुद्र का तापमान भी इससे बढ़ेगा और कई धरतों के अस्तित्व के लिए समुद्र संकट बन जाएगा। इसी सिलसिले में जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की अंतर-सरकारी समिति की ताजा रिपोर्ट के अनुसार सभी देश यदि जलवायु बदलाव के सिलसिले में हुई क्योटो-संधि का पालन करते हैं, तब भी वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2010 के स्तर की तुलना में 2030 तक 10.6 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। नतीजतन तापमान भी 1.5 से ऊपर जाने की आशंका बढ़ गई है। चूंकि विकासशील देश ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं, इसलिए उन्हें कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए विकसित देशों से आर्थिक मदद की जरूरत है। 'एडाप्टेशन गैस रिपोर्ट-2023 अंडर फायनेंस' में कहा गया है कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर एडाप्टेशन अर्थात् अनुकूलन के लिए जितनी वित्तीय मदद की जा रही है, उससे कई अधिक दस से 18 गुना आर्थिक मदद की जरूरत है। लेकिन अब अमेरिका के इस समझौते से अलग होने के बाद मदद की यह प्रकार नक्कारखाने की तृती साबित हो रही है।

छत्तीसगढ़ ही नहीं पड़ोसी राज्यों में भी छाया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जलवा



(पेज 1 से जारी)

जनता का मिला भरपूर आशीर्वाद

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछले वर्ष लगातार चुनावी सभाएं करते रहे हैं। इस दौरान उन्होंने तेज गमीं और लू की परवाह भी नहीं किया और वे लगातार जनता के बीच जाते रहे। उन्होंने प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर धुआंधार चुनावी प्रचार

कर न सिर्फ आमसभा को संबोधित किया, बल्कि कई चुनावी रैलियां भी कीं। वे जहां भी गए जनता का भरपूर रस्ते, प्यार और आशीर्वाद उन्हें मिला। इसके अलावा केन्द्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री साय की साफ स्वच्छ छवि का उपयोग छत्तीसगढ़ के बाहर मध्यप्रदेश, ओडिशा और झारखंड में किया। जहां उन्होंने एक के बाद एक 17 आमसभाएं और रोड शो की कमान संभाली। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री साय ने 12 कार्यक्रमों सम्मेलन, 54 जनसभा व रोड शो, 22 सामाजिक सम्मेलन किए। वहीं छत्तीसगढ़ के बाहर (मध्यप्रदेश, ओडिशा और झारखंड) 17 जनसभा एवं रोड शो, 24 सामाजिक सम्मेलन, 11 कार्यक्रमों सम्मेलन किए।

400 पार के लिए झोंकी पूरी ताकत

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें 400 से पार करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यही वजह है कि आत्मविश्वास से भरपूर मुख्यमंत्री साय छत्तीसगढ़ की सभी ग्यारह लोकसभा में जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे थे। साथ ही साय ने ओडिशा और झारखंड में भी भाजपा के पक्ष में भारी रूझान की बात की थी।

100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देश के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। छत्तीसगढ़

के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री साय बतौर सीएम बहुत कम समय में ही लोकप्रियता की सीढ़ी चढ़ने लगे हैं। उल्लेखनीय है कि मीडिया समूह 'इंडियन एक्सप्रेस' द्वारा जारी देश के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 77वें नंबर पर काबिज हैं। माना जा रहा है कि, मुख्यमंत्री ने अपने दो महीने के कार्यकाल में ही 'मोदी की गरंटी' लागू करने सहित कई उपलब्धियों से जनता के दिल में जगह बना ली है। मुख्यमंत्री साय अपने इस छोटें से कार्यकाल में न केवल आदिवासियों का, बल्कि आम जनता का विश्वास जीतने में सफल हुए हैं। यही वजह है कि उन्हें देश के प्रभावशाली लोगों की सूची में काफी ऊपर जाह मिली है।

नए भारतीय कानून नागरिक अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण कदम



आज की बात
प्रतीण कपकड़
स्वतंत्र लेखक

गणतंत्र दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हमारे देश के सपनों का जश्न है। ये वो दिन है जब हमने खुद को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। गणतंत्र दिवस पर नागरिक अधिकार और कर्तव्यों को याद करने का अवसर है। हमारा संविधान हमें सिर्फ अधिकार ही नहीं देता बल्कि कर्तव्य भी सौंपता है और इनका निर्वहन करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। 75वें और 76वें गणतंत्र दिवस के बीच इस वर्ष एक बड़ा बदलाव यह हुआ कि अब हमारे पास अपना कानून है। 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू हुआ था लेकिन हमने अपना भारतीय कानून इसके 75 साल बाद लागू किया। यह भारतीयता और नागरिक अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पहले हम ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानून को ही मान रहे



नागरिक अधिकार और कर्तव्यों को याद करने का अवसर है गणतंत्र दिवस

थे, 01 जुलाई 2024 को हमने अपना कानून लागू किया। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय सशस्त्र अधिनियम (बीएसए) के साथ लागू कानून न्याय व्यवस्था को और मजबूत कर रहा है, बल्कि देश को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति दिलाने वाला प्रभावी कदम रहा। यह कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाता है और सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। नए कानून को समझकर और अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूँ कि पुराना कानून ढंड पर केंद्रित था जबकि नया कानून न्याय सुनिश्चित करने पर जोर देता है। आजादी के बाद देश को गणतंत्र करने के लिए भारत की संविधान सभा ने करीब 3 साल की मेहनत करके दुनिया के सबसे प्रगतिशील संविधान में से एक संविधान की रचना की। उन्होंने भारत को एकांगी राष्ट्र बनाने की जगह गणराज्य बनाना तय किया। एक ऐसा संविधान जिसमें धर्म और जाति का भेद नहीं है, जिसमें अमीर और गरीब का भेद नहीं है, जिसमें स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। जो भारत के हर नागरिक को समानता की गारंटी देता है। और समानता की घोषणा करने के साथ ही समान अवसर देने का भी

इंतजाम करता है। इसीलिए भारत के संविधान में वंचित समुदायों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, दूरदराज के इलाकों के लिए स्वायत्तता की व्यवस्था है, बहुत सारे विषयों पर केंद्रीय कानून है तो बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन पर हर राज्य को अपनी सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से कानून बनाने की छूट है। गणतंत्र दिवस पर यही कहना चाहूंगा कि हमारा कर्तव्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाओं में पिछड़ों को मदद कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ें। हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति है। जो अपनी शिक्षा और कौशल से देश को आगे बढ़ा सकती है। हमें मिलकर समाज को अधिकारों के प्रति जागरूक करने, हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने और रोजगारों का सर्जन करने जैसे कई प्रयास करना होंगे। हमें देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए एकता के मूलमंत्र को समझना और चरितार्थ करना जरूरी है। आइये हम भारत के एक महान राष्ट्र होने पर गर्व करें। अपने संविधान और लोकतंत्र को कामयाब बनाने का संकल्प लें और इसमें अपने हिस्से का आहूति दें। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

पिछले साल के धान खरीदी का टूटा रिकार्ड धान खरीदी का आंकड़ा 145 लाख मीट्रिक टन से पार

-शशि पांडे
जगत प्रवाह, रायपुर। छत्तीसगढ़ में 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक के धान खरीदी में पिछले साल का रिकार्ड टूट गया है। पिछले वर्ष 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। इस वर्ष हुई धान खरीदी का आंकड़ा 145 लाख मीट्रिक टन से पार हो गया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 25 लाख 13 हजार किसान धान बेच चुके हैं। धान खरीदी के एवज में बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत अभी तक किसानों को 29 हजार 599 करोड़ रूपए

का भुगतान किया गया है। धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मीलिंग के लिए तेजी के साथ धान का उठाव किया जा रहा है। अभी तक 110 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी कर दिया गया है। जिसके विरुद्ध 87 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव हो चुका है। धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। प्रदेश के समस्त पंजीकृत कृषकों को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान विक्रय हेतु टोकन की सुविधा ऑनलाईन एप्प (टोकन तुंहर हाथ) एवं उपाजर्न केन्द्रों में 25 जनवरी 2025 तक के लिए उपलब्ध कराया गया है। किसान

सुविधा अनुसार तिथि का चयन कर नियमानुसार धान विक्रय कर सकते हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा इस खरीफ वर्ष के लिए 27.78 लाख किसानों द्वारा पंजीजन कराया गया है। इसमें 1.59 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपाजर्न केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है। राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य की तहत 24 जनवरी को 30 हजार 762 किसानों से 1.41 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसके लिए 58 हजार 997 टोकन जारी किए गए थे।

अवैध धान परिवहन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 280 कट्टा धान जब्त

-आनंद शर्मा
जगत प्रवाह, रायपुर। महासमुंद जिले के बागबाहरा के सीमा जांच चौकी नर्रा (कोमाखान) पर अवैध धान परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 280 कट्टा धान जब्त किया। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी उमेश कुमार साहू के मार्गदर्शन में रात 12 बजे की गई। जांच के दौरान, वाहन चालक धान परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं दे

सका। इस कारण मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर लिया और धान से लदे वाहन को कृषि उपज मंडी समिति बागबाहरा की अधिकार में सौंप दिया। इसके अलावा, कोमाखान तहसील के बाधामुड़ा समिति में निरीक्षण के दौरान तीन किसानों का धान गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरा। कुल 170 क्विंटल धान की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर उसे वापस लौटा दिया गया।

प्रशासन ने यह कदम खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और किसानों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उठाया है। अधिकारियों ने कहा है कि धान के अवैध परिवहन और खराब गुणवत्ता वाले धान के मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों और व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



पत्रकारों की ताकत उनकी कलम है: जितेन्द्र गेहलोत, पूर्व विधायक

-प्रमोद बरसले
जगत प्रवाह, टिहठगी। राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत एवं श्रमजीवी पत्रकार संघ के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन स्वर्णकार समाज की धर्मशाला में सम्पन्न हुआ। जिसमें मुख्य अतिथि जितेन्द्र गहलोत पूर्व विधायक अलाउद्दीन ने अपने उद्बोधन में कहा कि पत्रकारों की ताकत उनकी कलम है। वह अपनी कलम से हमें समाज में हो रही अच्छाइयों और बुराइयों से परिचित करवाते हैं और किसी भी घटना की सत्यता को हमारे सामने लाते हैं। आज के दौर में महिला पत्रकार भी बखूबी पत्रकारिता का निर्वहन कर रही है। पत्रकारिता के क्षेत्र में समाचारों के कवरेज के लिए वह भी पीछे नहीं हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत के महानियंत्रक केसी यादव उज्जैन ने कहा कि हमारा संगठन समय-समय पर पत्रकारों की हितों की लड़ाई लड़ता है। सदैव हमारा संगठन सभी पत्रकारों के साथ खड़ा हुआ है। इसी के साथ राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत द्वारा पत्रकार सुरक्षा हेतु मीडिया प्रकोष्ठ का गठन किया गया। गठन के साथ ही रायपुर छत्तीसगढ़ इकाई

द्वारा पांच हजार रूपए राशि प्रदान की गई। विशेष अतिथि भाजपा विधानसभा संयोजक नंदन राज जैन ने कहा कि आज प्रतिस्पर्धा के दौर में पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी चुनौतियां भी हैं। ताल नगरपरिषद अध्यक्ष मुकेश परमार ने कहा एक पत्रकार के जीवन में काफी चुनौतियां आती हैं। फिर भी एक सच्चा पत्रकार उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते जाते हैं। भाजपा जिला उपाध्यक्ष उपेन्द्र सिंह यादव ने कहा कि पत्रकारों का जीवन काफी जोखिम भरा रहता है। फिर भी पत्रकार अपने कार्य को बखूबी अंजाम देते हैं और सच्चाई जनता के सामने लाते हैं। मंच पर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश कोठारी भी उपस्थित थे कार्यक्रम को अनिल देसरला उपाध्यक्ष जैन मालवा महासभा राष्ट्रीय गोवर्धन गोशाला अध्यक्ष मनीष सेठिया बदनावर से अल्लफा मसूरी पत्रकार मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर देवेन्द्र कुमार शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से भारत सोनी रामसिंह नायक दिनेश साहू कुणाल गुप्ता राजस्थान से राधेश्याम काला लोकेश मकवाना अमित अग्रवाल चोमेला मंदसौर से पूनम शर्मा ताल से मनोज शर्मा आदि अनेक पत्रकारों ने संबोधित किया।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें...

लोक निर्माण विभाग नर्मदापुरम (म.प्र.)



निर्माण उच्च गुणवत्ता का आधार

गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें...



जल संसाधन नर्मदापुरम (म.प्र.)

जल ही जीवन है

गणतंत्र दिवस की
शुभकामनायें...

भारत पेपर इण्डस्ट्रीज नर्मदापुरम (म.प्र.)

जीवन में शिक्षा अनमोल है

गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें...

जिला अस्पताल नर्मदापुरम (म.प्र.)

स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है

गणतंत्र दिवस की
शुभकामनायें...

खनिज विभाग नर्मदापुरम (म.प्र.)

प्रकृति हमारे जीवन का आधार

गणतंत्र दिवस की
शुभकामनायें...

आबकारी विभाग नर्मदापुरम (म.प्र.)

मिलावट से बचें

गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें...



रेशम उद्योग नर्मदापुरम (म.प्र.)

धागा हर कड़ी जोड़ता है

गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें...



नगर पालिका परिषद नर्मदापुरम (म.प्र.)

समस्त करो का भुगतान समयावधि में करें